फैसला ◆ प्रति परिवार 6 किलो चीनी मिलेगी 13.50 रुपये प्रति किलो पर

दिल्ली में राशन पर गरीबों को मिलती रहेगी सस्ती चीनी

दिल्ली सरकार हर महीने खुले बाजार से खरीदेगी 2,200 टन चीनी

प्रेट्र ◆ नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने राशन की दुकानों के जरिये 3.64 लाख गरीब परिवारों को 13.50 रुपये प्रति किलो की दर पर चीनी का वितरण जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग का डिकंट्रोल करने के साथ ही चीनी की सप्लाई बंद कर दी है।

केंद्र सरकार की डिकंट्रोल नीति के तहत राज्यों को खुले बाजार से खुद चीनी खरीदनी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत बिक्री मूल्य और एक्स-फैक्ट्री मूल्य 32 रुपये प्रति किलो के बीच का अंतर सब्सिडी के रूप में केंद्र वहन करेगा और इसका भुगतान राज्यों को करेगा। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बताया कि राज्य कैबिनेट के फैसला के मुताबिक पीडीएस के तहत बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशनकार्ड धारकों को रियायती मूल्य पर चीनी का वितरण पूर्ववत जारी रहेगा।

केंद्र सरकार ने पिछले मई में चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त किया था और मिलों को लेवी चीनी देने की बाध्यता से मुक्त कर दिया था। इससे पहले तक मिलों को अपना दस फीसदी उत्पादन सस्ती दर पर सरकार को देना होता था। सरकार राशन की दुकानों के जरिये इसी चीनी का वितरण करती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा से ही हम समाज के गरीब तबके का ख्याल करते रहे हैं। इसी वजह से हमने चीनी वितरण की स्कीम को बंद न करने का फैसला किया है। सरकार हर महीने खुले बाजार से 2,200 टन चीनी की खरीद करेगी। यह खरीद दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि. द्वारा बिडिंग के जरिये की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बीपीएल और अंत्योदय योजना के तहत कार्डधारकों को पूर्ववत चीनी मिलती रहे। गरीब उपभोक्ताओं को हर महीने प्रति कार्ड 6 किलो चीनी मिलती रहेगी। कैबिनेट ने मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद के लिए एचएलएल लाइफकेयर लि. की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार की यह सार्वजनिक कंपनी दिल्ली के अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों के लिए मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद करेगी। दिल्ली सरकार ने 1999 में स्वास्थ्य विभाग के तहत इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट सेल गठित किया था। अभी तक यह सेल उपकरणों की खरीद कर रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सिस्टम से उपकरणों की खरीद, स्थापना और रखरखाव में बाधाएं आ रही हैं। इसी वजह से कैबिनेट ने एचएलएल लाइफकेयर के जरिये खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उपकरणों की खरीद के लिए विशेषज्ञ खरीद एजेंसी की जरूरत महसूस की गई थी। एचएलएल ने उपकरणों से जुड़ी सभी सेवाएं देने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री के अनुसार कैबिनेट ने दक्षिण दिल्ली के सरिता विहार में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस अस्पताल में इमर्जेंसी, सेवाओं के अलावा मेटरनिटी, सर्जिकल और अन्य विशेषज्ञ मेडिकल सेवाएं मिलेंगी। केबिनेट ने दिल्ली सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को विषम स्थिति में वित्तीय सहायता देने के लिए पत्रकार कल्याण योजना को भी मंजूर दी है। दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसायटी के अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट फैसले

- एचएलएल लाइफकेयर के जरिये मेडिकल उपकरण खरीद को मंजूरी
- सरिता विहार में 100 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण को भी हरी झंडी
- एड्स कंट्रोल सोसायटी के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिलेगी
- पत्रकारों को वित्तीय मदद देने के लिए कल्याण योजना

Business Bhaskar

10/7/13

MN